प्रदेश के 176 औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े बदलाव की है तैयारी

समयबद्ध विकास, भूमि का बेहतर उपयोग और निवेशक अनुकूल सुधार पर जोर

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ/कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने राज्य को दस खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से उद्योग जगत के साथ एक व्यापक वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की। मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 176 औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य जोर समयबद्ध सेवा-प्रदान, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, भूमि संसाधनों के बेहतर उपयोग और डिजिटल प्रक्रियाओं के उन्नयन पर रहा।

बैठक में भूमि आवंटन, हस्तांतरण, भू-उपविभाजन और भवन मानचित्र स्वीकृति से जुड़ी सेवाओं को सरल व पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को आवेदनों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए।

प्राधिकरण ने निवेश मित्र 3.0 के माध्यम से सभी ई-सेवाओं को एकीकृत करने, पर्यावरण, श्रम और भवन अनुमति प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा भूमि आवंटन व ई-नीलामी को पूरी तरह स्वचालित करने की घोषणा की। यूपीसीडा ने तेज विकास, पारदर्शिता और निवेशक-हितैषी सुधारों की महत्वाकांक्षी योजनाएं पेश कीं। दूसरी ओर उद्योग जगत ने कार्यों के त्वरित क्रियान्वयन, जमीनी अवसंरचना सुधार और डिजिटल प्रक्रियाओं की सुगमता पर जोर देते हुए सहयोग का भरोसा जताया।

भूमि बैंक का उत्पादक उपयोग

प्राधिकरण ने औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि बैंक के संतुलित और उत्पादक उपयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्राधिकरण उन सेक्टरों और क्षेत्रों को प्राथमिकता देगा जहां उद्योग लगने से अधिक रोजगार, निवेश और औद्योगिक वृद्धि संभव हो। अधिकारियों को उभरते उद्योगों और उच्च संभावनाओं वाले सेक्टरों को तत्काल भूमि आवंटन के अवसरों की पहचान करने का निर्देश दिया गया।

औद्योगिक क्षेत्रों में अवसंरचना को संतृप्त करने का लक्ष्य : यूपीसीडा ने राज्य के सभी 176 औद्योगिक क्षेत्रों को सड़क, नालियां, सीवरेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइटिंग, बिजली आपूर्ति, जलापूर्ति और नागरिक सुविधाओं से पूरी तरह संतृप्त करने का लक्ष्य रखा है। क्षेत्रीय प्रबंधकों को एक सप्ताह में स्थलीय आवश्यकता सर्वेक्षण और संशोधित लागत प्रस्ताव जमा करने को कहा गया है। कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राइट्स को थर्ड पार्टी एजेंसी नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी चरणबद्ध निरीक्षण करेंगे। कचरा प्रबंधन व सफाई से जुड़े वार्षिक अनुरक्षण अनुबंधों में भी पारदर्शिता और प्रदर्शन मानकों को जोड़ा जाएगा।

औद्योगिक नीतियों का प्रचार करें : बैठक में वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2024, औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति, एमएसएमई नीति, ओडीओपी आधारित प्रोत्साहन तथा आईटी आईटीईएस नीति पर चर्चा की गई। अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई कि वे नीतियों को उद्योगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाएं और कार्यशालाएं आयोजित करें।